

उम्मीदों की चर्ताक

राह हो तो सफर भी शुरू हो जाता है और मुसाफिर भी निकल पड़ते हैं। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार के तीसरे भूमि पूजन समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) में आए निवेश प्रस्ताव सफर और मुसाफिर की इसी मनःस्थिति और प्रदेश की नए सिरे से संवरती तस्वीर का दर्शन कराते हैं। प्रदेश को मलाल रहा है कि दिल्ली की नजदीकी का लाभ जितना एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को मिला उतना दूसरे हिस्सों को नहीं मिला। प्रदेश की सरकारों ने भी क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। विशेष तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड के क्षेत्रों के लिए विकास सपना ही रहा है, लेकिन अब यहां उम्मीद की चमक नजर आ रही है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' मंत्र के अनुरूप जो आधारभूत ढांचा सृजित किया, अब उसका परिणामी लाभ दिखाई देने लगा है।

यह अलग बात है कि अकेले गौतमबुद्ध नगर ने 45,529.29 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अपनी झोली में डाल लीं, लेकिन इसके बाद अन्य जिलों की बात करें तो सर्वाधिक परियोजनाएं लखनऊ और गोरखपुर जिले के हिस्से में आई हैं। एक मध्य उत्तर प्रदेश का केंद्र जिला है तो दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश की धड़कन। यही नहीं जिन 29 सबसे बड़ी परियोजनाओं पर सबकी नजर थी, उनमें से दो कुशीनगर जैसे जनपद की रहीं। कुशीनगर में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडा शुरू हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की भूमिका भी निवेशकों को यहां तक लाने में अहम रही है। कनेक्टिविटी विकास के गढ़ की पहली आवश्यकता रही है। पिछली सरकार में एक्सप्रेस-वे की जो परियोजनाएं शुरू हुई या पूरी हुई उन्होंने निवेशकों को गंतव्य की स्पष्ट पहचान करा दी है। बुंदेलखण्ड के खाते में अन्य हिस्सों को देखते हुए ज्यादा बड़ी परियोजनाएं भले न आई हों, लेकिन अतीत की अपेक्षा उत्साहवर्धक बाद उम्मीद की जा रही है कि विकास यात्रा में यह हिस्सा भी अपनी दावेदारी बढ़ावदेकर साबित करेगा। सबका साथ, सबका विकास की दिशा में बढ़ा

पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड के क्षेत्रों के लिए विकास सपना ही रहा है, लेकिन अब यहां उम्मीदों की चमक नजर आ रही है।